

वैदेशिक क्षेत्र

चालू वर्ष में सामान्य व्यापार और चालू खाता घाटा, विपुल वित्तीय प्रवाह, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि तथा स्थिर मुद्रा दर संचलन का सुदृढ़ वैदेशिक क्षेत्र परिणाम उस सामर्थ्य और लचीलेपन के पथ पर वापसी की ओर संकेत करता है जो वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से पूर्व विद्यमान था। इसके चलते पिछले वर्ष सुधार आया जिसे अत्यधिक दबाव के आरम्भिक चरण में ही तथा नीतिगत अनुक्रियाओं की सामर्थ्य पर हासिल किया गया था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कच्चे पेट्रोलियम के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में सुधार, डीजल के मूल्यों के विनियंत्रण में सहायक हुआ है। समग्र व्यापार निष्पादन ने स्वर्ण आयात पर प्रतिबंध को हटाने के लिए उचित समय होने का संकेत दिया। लचीलापन, व्यापार विविधीकरण प्रक्रिया का भी भाग रहा। जबकि व्यापार और चालू खाता घाटा की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ है, वित्तपोषण की अपेक्षा से अधिक वित्तीय अंतर्वाह की प्रचुरता के कारण विदेशी मुद्रा भंडार (जनवरी, 2015 के अन्त में 328.7 बिलियन अमरीकी डालर) को सुदृढ़ करने में मदद मिली है। ये कारक कमजोरी की उन चिन्ताओं को कम करने में सहायक हुए हैं जिनकी वजह से पिछले वर्ष अत्यधिक दबाव रहा था। तथापि, इन चिन्ताओं से एक प्रबल नकारात्मक खतरा रहता है, क्या किसी कारणवश वैश्विक वातावरण की स्थिति खराब होनी चाहिए। वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण कुछ अनिश्चित सा किन्तु स्थिर रहता है और इससे सामर्थ्य प्राप्त होने की संभावना होती है, यदि कच्चे पेट्रोलियम के निम्नतर मूल्यों के कारण महत्वपूर्ण उभरती बाजार की अर्थव्यवस्थाओं में मांग सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है।

वैश्विक आर्थिक वातावरण

4.2 कच्चे पेट्रोलियम के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में तेजी से आई हालिया गिरावट के साथ वैश्विक आर्थिक वातावरण का झुकाव बेहतर परिवर्तन की ओर प्रतीत होता है। इससे मौद्रिक समायोजन से क्रमिक आहरण के बावजूद अमरीकी अर्थव्यवस्था में वैश्विक समग्र मांग और तेजी से सुधार को प्रोत्साहन मिलने की आशा है। 2008 के वैश्विक संकट के पश्चात्, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अनिश्चितता और यूरो युग में, खासकर 2011 से, दीर्घकालिक कमजोरी का खतरा मंडराने लगा इससे अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने अपने वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) में प्रायः वैश्विक विकास को अधोगामी संशोधित किया। 20 जनवरी, 2015 को प्रकाशित अपने अपडेट में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने

वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर 2014 में 3.3 प्रतिशत से बढ़कर 2015 में 3.5 प्रतिशत होने और 2016 में और भी बढ़कर 3.7 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया। अक्टूबर, 2014 के इसके अनुमानों से इस अधोगामी संशोधन का कारण चीन, रूस, यूरो क्षेत्र, जापान और तेल के मूल्यों में तेजी से आई गिरावट के कारण कुछ बड़े तेल निर्यातकों में कमजोर आर्थिक संभावनाएं रहीं। संयुक्त राज्य अमरीका ऐसी एक मात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है जिसके संबंध में 2015 के लिए विकास अनुमानों को 0.5 प्रतिशतांक बढ़ाकर 3.6 प्रतिशत कर दिया गया है।

4.3 उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई), जो मामूली घरेलू मांग और संरचनात्मक बाधाओं के चलते विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष कर रही हैं, के

मामले में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपडेट, विकास अनुमानों को 2015 में 4.3 प्रतिशत और 2016 में 4.7 प्रतिशत पर स्थिर करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के मूल्यों में गिरावट, निवल प्रभाव और निकटवर्ती दृष्टिकोण को केवल आंशिक रूप से प्रतिबिम्बित करते हैं। आगे चलकर, ईएमडीई के लिए इसके और अधिक अनुकूल होने की संभावना है। ये वैश्विक उत्पाद (क्रय-शक्ति की समानता के दृष्टिगत) का आधे से अधिक बैठते हैं और जिन्होंने मुद्रास्फीति उच्च रहने के साथ वैश्विक विकास में अत्यधिक योगदान दिया है। इसका परिणाम अनुमानित से बेहतर हो सकता है। तेल मूल्य आपूर्ति आघात प्रभाव की संभावित अवधि के साथ-साथ यूरो के क्षेत्र में संभावित और भी मंदी की संभावना के साथ वित्तीय बाजारों में अचानक सुधार और विकास संबंधी अधोगामी खतरे कुछ ऐसी चिन्ताएं हैं जो बढ़ती जा रही हैं।

4.4 वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक अपडेट वर्ष 2015 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद विकास 6.3 प्रतिशत होने (इब्ल्यूईओ के अक्टूबर, 2014 की तुलना में 0.1 प्रतिशतांक का अधोगामी संशोधन) और वर्ष 2016 के लिए विकास 6.5 प्रतिशत होने का अनुमान करता है, जो चीन के अनुमानित विकास 6.3 प्रतिशत से अधिक है। 30 जनवरी, 2015 को केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा किए गए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के हालिया ऊर्ध्वगामी संशोधन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के डब्ल्यूईओ के अनुवर्ती अनुमानों में प्रतिबिम्बित किए जा सकते हैं। वैश्विक आर्थिक कार्यकलाप के स्तर का, व्यापार माध्यमों के जरिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं की विकास संभावनाओं से महत्वपूर्ण सीधा संबंध होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक अपडेट, जनवरी, 2015 के अनुसार, विश्व व्यापार खंड विकास का अनुमान वर्ष 2015 और 2016 के लिए क्रमशः 3.8 प्रतिशत और 5.3 प्रतिशत नियत किया गया है जो क्रमशः 1.1 प्रतिशतांक से 0.2 प्रतिशतांक तक कम है।

भारतीय व्यापारिक माल व्यापार

4.5 विगत दस वर्ष से, भारतीय व्यापारिक माल व्यापार (सीमाशुल्क आधार पर) 2004-05 में 195.1 बिलियन अमरीकी डालर से 2013-14 में बढ़कर 764.6 बिलियन अमरीकी डालर होकर कई गुना बढ़ गया है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार, वैश्विक निर्यात और आयात में भारत का हिस्सा वर्ष 2004 में क्रमशः 0.8 प्रतिशत और 1.0 प्रतिशत से 2013 में बढ़कर क्रमशः 1.7 प्रतिशत

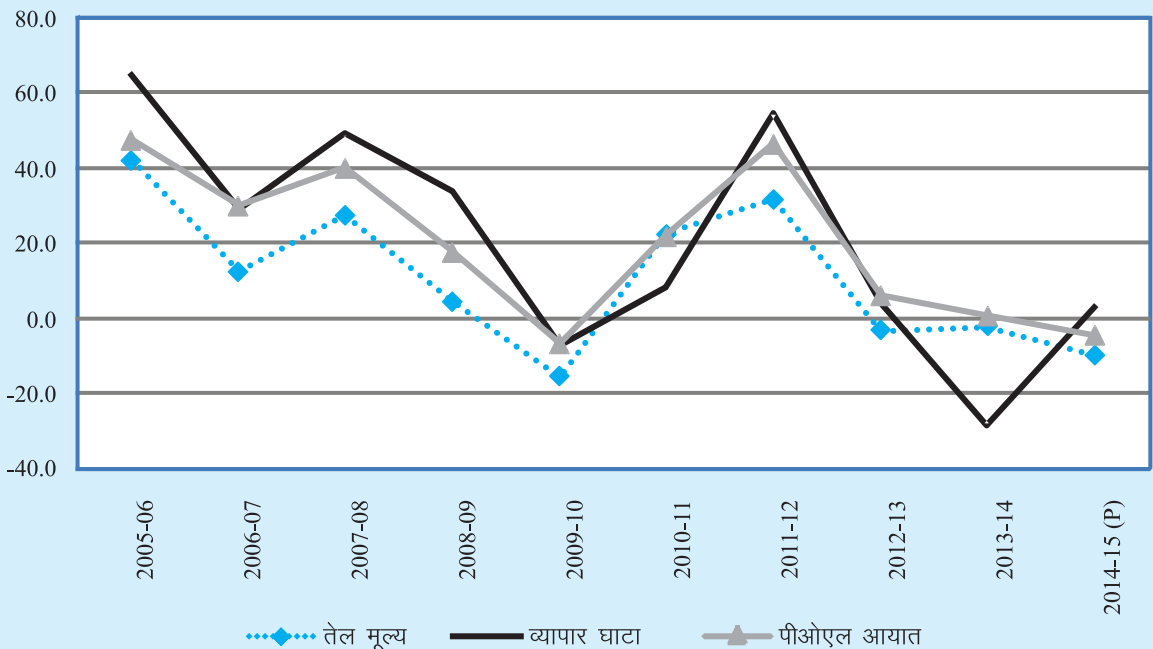
और 2.5 प्रतिशत हो गया है। प्रमुख निर्यातकों और आयातकों की दृष्टि से इसका स्थान वर्ष 2004 में क्रमशः 30 और 23 से सुधरकर 2013 में क्रमशः 19 और 12 हो गया है। जहां सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात के रूप में कुल भारतीय व्यापारिक माल व्यापार 2004-05 में 29.0 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 41.8 प्रतिशत हो गया है, वहीं इन्हीं दो अवधियों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में भारतीय व्यापारिक माल निर्यात 12.1 प्रतिशत से बढ़कर 17.0 प्रतिशत हो गया है। इन दो अवधियों के भीतर विकास में अत्यधिक अंतर रहे, इसका काफी हद तक कारण वैश्विक अनिश्चितता, कुछ क्षेत्रों में दीर्घकालिक कमजोरी और 2008 से वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता रही। विशेष रूप से, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के मूल्य, व्यापारिक माल व्यापार घाटे के उच्च स्तरों की प्रक्रिया में एक प्रमुख कारक रहे (बॉक्स 4.1)।

4.6 2010-11 में 40.5 प्रतिशत की अत्यधिक उच्च वृद्धि को दर्ज करने के पश्चात्, 2011-12 में व्यापारिक माल निर्यात सामान्य अर्थात् 21.8 प्रतिशत रहा। दो वर्ष में उच्च वृद्धि से समग्र निर्यात 300 बिलियन अमरीकी डालर के निशान को पार कर गया। 2012-13 में, यद्यपि निर्यात अभी भी 300 बिलियन अमरीकी डालर के निशान से ऊपर था, किन्तु यह निर्यात वृद्धि जारी नहीं रखी सकी और इसमें 1.8 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई [परिशिष्ट 7.1 (ख)]। तथापि, 2013-14 के दौरान, निर्यात वृद्धि में 4.7 प्रतिशत (314.4 बिलियन अमरीकी डालर) का सुधार हुआ। 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में निर्यात वृद्धि कुछ हद तक सामान्य 2.4 प्रतिशत (पिछले वर्ष की इसी अवधि में 258.7 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 265.0 बिलियन अमरीकी डालर) रही।

4.7 2010-11 में भारत के व्यापारिक माल आयात में 28.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और सोने तथा चांदी, पेट्रोलियम, पीओएल समूह और पीओएल-भिन्न तथा सोने और चांदी-भिन्न आयात में मोटे तौर पर हुई वृद्धि के आधार के चलते पूरे 2011-12 के दौरान उच्च विकास दर जारी रही। 2012-13 में, सोने और चांदी तथा पीओएल भिन्न आयात की वृद्धि दरों में केवल मामूली गिरावट आई, जिससे कुल आयात का लगभग 490 बिलियन अमरीकी डालर का उच्च स्तर जारी रहा। 2013-14 में, घरेलू और वैदेशिक कारकों के चलते रुपये के तीव्र अवमूल्यन के मद्देनजर, सरकार ने स्वर्ण आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जिससे उसमें 46.4 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आई। घरेलू कार्यकलाप के कमजोर रहने के साथ

बॉक्स 4.1 : वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के मूल्य में घट-बढ़ के निहितार्थ

वैश्विक स्तर पर वस्तु खासकर कच्चे तेल के मूल्यों में किसी भी बड़े परिवर्तन के वैदेशिक क्षेत्र के लिए निहितार्थ होते हैं क्योंकि भारत शेष विश्व के साथ तेजी से एकीकृत हो रहा है। यह स्पष्ट है कि विगत दस वर्ष में जीडीपी के अनुपात में भारत का बढ़ता दुतरफा वैदेशिक क्षेत्र लेन-देन दुगने से भी अधिक हो गया है। व्यापार में खुलापन अधिक निर्यात के जरिए उच्चतर विकास के अवसर प्रदान करता है और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद घरेलू स्तर पर उपलब्ध कराता है। विशिष्ट रूप से आर्थिक भाषा में, चालू खाता घाटे को उस विदेशी बचत के रूप में देखा जाता है जो ईएमडीई में घरेलू बचतों के नियत स्तर से अपेक्षाकृत अधिक निवेश के जरिए विकास को बढ़ाता देता है; किन्तु भारत की तेल आयात पर व्यापक निर्भरता और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के मूल्यों में तेजी से बढ़तीरी के संदर्भ में, 2011-12 और 2012-13 में चालू खाता घाटे का बढ़ना एक विशिष्ट परिणाम हो सकता है। कच्चे तेल के मूल्यों में परिवर्तन का भारत के चालू खाता घाटे से सीधा संबंध होता है। मूल रूप से, कच्चे तेल का आयात देश के कुल आयात का एक काफी बड़ा भाग बैठता है। हालिया वर्षों में पेट्रोलियम, ऑयल लुब्रिकेन्ट्स (पीओएल) आयात भारत के कुल आयात का एक-तिहाई से अधिक बैठता है। 2013-14 में, पीओएल आयात कुल आयात का 36.6 प्रतिशत बैठता है। चालू वित्त वर्ष में अब तक (दिसम्बर 2014 तक) कुल आयात में पीओएल आयात का हिस्सा 33 प्रतिशत आंका गया है। हालिया वर्षों में व्यापार घाटे में परिवर्तन और चालू खाता घाटे के निहितार्थों को कच्चे तेल के मूल्यों में परिवर्तनों द्वारा व्यापक रूप से स्पष्ट किया गया है (चित्र 1)।

चित्र 1: तेल मूल्य (भारतीय समूह) पीओएल आयात और व्यापार घाटे में परिवर्तन (प्रतिशत)

टिप्पणी: वर्ष 2014-15 के संबंध में आंकड़े अप्रैल-दिसंबर से संबंधित हैं।

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल का मूल्य (भारतीय समूह) जो 2014-15 की पहली तिमाही में 107.2 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल था, वह 2014-15 की दूसरी तिमाही में घटकर 101.7 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल और तीसरी तिमाही में घटकर 75.2 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल रह गया है। तत्पश्चात्, यह 50 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया है। 30 जनवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार, भारतीय समूह का कच्चे तेल का मूल्य 46.7 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल पर स्थिर रहा। कुछ सरलीकृत संभावनाओं के तहत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के मूल्यों में 1 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल की कमी आने पर निवल आयात बिल 0.9 बिलियन अमरीकी डॉलर प्रति वर्ष तक कम होने की संभावना है। अप्रैल, 2014 से जनवरी, 2015 की अवधि में तेल का औसत मूल्य लगभग 90 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल था, जिसमें 2014-15 के लिए समग्र निवल तेल आयात में 9.5 बिलियन अमरीकी डॉलर तक कमी आने की संभावना है, इससे यह माना जाता है कि आयात की मात्रा में 6 प्रतिशत की वृद्धि होगी। मार्च, 2014 की तुलना में जनवरी, 2015 में भारतीय समूह के कच्चे तेल के मूल्य में लगभग 56 प्रतिशत की अत्यधिक गिरावट के दृष्टिगत, भारत के चालू खाता संतुलन को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण की कीमत में 10 अमरीकी डॉलर प्रति ट्राय आउंस तक की कमी आने से 2014-15 के लिए रत्न और आभूषण के निवल आयात में 130 बिलियन अमरीकी डॉलर वार्षिक की गिरावट आने की संभावना तो है, किन्तु इससे आयात की मात्रा में किसी परिवर्तन की संभावना नहीं है।

पीओएल-भिन्न और सोने तथा चांदी-भिन्न कारोबार में भी लगभग 7 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसके चलते समग्र आयात घटकर 450 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया।

2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में आयात 2013-14 (अप्रैल-जनवरी) में 375.3 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 383.4 बिलियन

अमरीकी डालर हो गया। जबकि 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में पीओएल आयात मूल्य में 7.9 प्रतिशत की गिरावट आई, 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में सोने और चांदी के आयात में 8.0 प्रतिशत वृद्धि हुई, पीओएल-भिन्न और सोने तथा चांदी-भिन्न आयात, जो औद्योगिक कार्यकलाप के लिए आवश्यक आयात को व्यापक रूप से दर्शाता है, में 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह वृद्धि 2012-13 और 2013-14 में क्रमशः 0.7 प्रतिशत तथा 6.9 प्रतिशत की कमी दर्ज करने के पश्चात् हुई।

4.8 जबकि मामूली तौर पर उपर्युक्त गतिविधियां मोटे तौर पर प्रवृत्तियां प्रस्तुत करती हैं, गुणवत्ता और मूल्य, जिन्हें व्यापार की शर्तों को दर्शाने वाली मात्रा और इकाई मूल्य सूचकांकों द्वारा श्रेष्ठ तरीके से इंगित किया जाता है, में परिवर्तनों की दृष्टि से वृद्धि दरों पर विश्लेषण करना उपयोगी है (सारणी 4.1)। निर्यात संबंधी मात्रात्मक सूचकांक में मोटे तौर पर अमरीकी डॉलर में मामूली वृद्धि के चलते रुपये की अति अल्प दरों के साथ दिशात्मक रूप से इसके अनुरूप परिवर्तन होता है। 2012-13 इसका अपवाद रहा जब अमरीकी डालर के दृष्टिगत मात्रात्मक सूचकांक में उच्च सकारात्मक दरों के विपरीत वृद्धि दर प्रतिकूल रही। आयात

के मात्रात्मक सूचकांक के मामले में, अमरीकी डॉलर और रुपये में अभिव्यक्त मामूली वृद्धि दरों के साथ और अधिक दिशात्मक विविधता रही।

4.9 2009-10 के अपवाद के साथ, मोटे तौर पर सकारात्मक क्षेत्र में निर्यात और आयात के इकाई मूल्य सूचकांक में परिवर्तन हुआ। 2011-12 में व्यापार की दृष्टि से परिणाम की स्थिति बदहाली का साक्ष्य रही। इस बदहाली का कारण तेल मूल्य का आघात रहा जो 2014-15 की दूसरी छमाही में विपरीत हो सका था।

4.10 वृहत आयात निर्भरता के चलते तेल मूल्य का आघात जबरदस्त रहा जिसकी वजह से 2011-12 से आयात का स्तर उच्च रहा और सापेक्ष मंदी की वैश्विक मांग से समग्र निर्यात वृद्धि बाधित हुई। भारत के अनुवर्ती लचीलेपन के कारण ऐसी विभिन्न प्रक्रियाएं हुईं जिनके दायरे में पण्य संरचना और व्यापार की दिशा दोनों ही आते हैं।

व्यापार की संरचना

4.11 भारतीय व्यापार की वस्तुगत संरचना में उदारीकरण के समय से अनेक फेरबदल हो गए हैं और ये व्यापार नीति,

सारणी 4.1 : व्यापार निष्पादन: मात्रा और इकाई मूल्य सूचकांक

(प्रतिशत परिवर्तन)

	निर्यात				आयात				व्यापार की स्थिति	
	अमरीकी डालर	रुपये	मात्रा सूचकांक	इकाई मूल्य सूचकांक	अमरीकी डालर	रुपये	मात्रा सूचकांक	इकाई मूल्य सूचकांक	निवल	आय
2001-02	-0.6	2.7	0.8	1.0	2.9	6.2	4.0	2.8	-1.7	-0.9
2002-03	20.3	22.1	19.0	2.9	19.4	21.2	5.8	14.3	-10.0	7.2
2003-04	21.1	15.0	7.3	7.5	27.3	20.8	17.4	3.1	4.3	11.9
2004-05	30.8	27.9	11.2	14.9	42.7	39.5	17.2	18.9	-3.4	7.4
2005-06	23.4	21.6	15.1	6.1	33.8	31.8	16.0	14.0	-6.9	7.1
2006-07	22.6	25.3	10.2	13.7	24.5	27.3	9.8	15.1	-1.2	8.8
2007-08	29.0	14.7	7.9	5.1	35.5	20.4	14.1	1.9	3.1	11.2
2008-09	13.6	28.2	9.0	16.9	20.7	35.8	20.2	13.8	2.7	11.9
2009-10	-3.5	0.6	-1.1	1.0	-5.0	-0.8	9.9	-10.0	12.3	11.0
2010-11	40.5	35.2	15.2	13.8	28.2	23.4	8.0	13.0	0.7	15.9
2011-12	21.8	28.3	8.9	20.2	32.3	39.3	-20.9	74.9	-31.3	-25.2
2012-13	-1.8	11.5	7.9	6.0	0.3	13.8	6.1	8.0	-1.9	5.8
2013-14	4.7	16.6	5.9	9.9	-8.3	1.7	-10.7	12.9	-2.7	3.1
2014-15(अ)	3.4	5.0	4.8	3.6	1.5	3.9	0.8	3.3	0.2	5.0

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएण्डएस) के आंकड़ों के आधार पर संगणित।

टिप्पणी : वर्ष 2014-15 के लिए विकास दर अप्रैल-सितम्बर से संबंधित है। अ: अनंतिम

अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में घट-बढ़ और घरेलू मांग के बदलते स्वरूप से प्रेरित रहे हैं। हालिया वर्षों में विनिर्मित मालों के निर्यात का बढ़ा हिस्सा 63 प्रतिशत से अधिक है। इसके बाद अशोधित और पेट्रोलियम उत्पादों (कोयला सहित) का निर्यात में हिस्सा 20 प्रतिशत है तथा कृषि और संबद्ध उत्पादों का हिस्सा 13.7 प्रतिशत है (परिशिष्ट सारणी 7.3(ख))। 2014-15 (अप्रैल-दिसम्बर) में, शीर्ष 7 उत्पाद समूहों में भारत के कुल निर्यात का हिस्सा लगभग 80.9 प्रतिशत बैठता है: पेट्रोलियम उत्पाद (19.4 प्रतिशत हिस्सा); रत्न और आभूषण (13.0 प्रतिशत हिस्सा); कृषि और संबद्ध उत्पाद (12.0 प्रतिशत हिस्सा); वस्त्र और संबद्ध उत्पाद (11.6 प्रतिशत हिस्सा); रसायन और संबद्ध उत्पाद (10.1 प्रतिशत हिस्सा); परिवहन उपकरण (8.5 प्रतिशत हिस्सा); और मशीनरी (6.3 प्रतिशत हिस्सा)।

4.12 पेट्रोलियम और कृषि तथा संबद्ध उत्पादों के निर्यातों में बढ़ोतरी जो विगत चार वर्षों में सकारात्मक रही थी, 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में नकारात्मक हो गयी। रत्न और आभूषण निर्यात जिनमें 2012-13 और 2013-14 में गिरावट के रुझान दिखे, 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में कमी के रुझान दर्ज किए गए। इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यातों में, 2012-13 से निरंतर ह्रास होता रहा है। 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान कुछ क्षेत्रों जैसे कि परिवहन उपकरण, मशीनरी, रसायनों और संबद्ध उत्पादों, वस्त्र और संबद्ध उत्पादों तथा बेस धातुओं के निर्यातों जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

4.13 2012-13 और 2013-14 और 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान, समुद्री उत्पादों और चमड़े तथा चमड़ों से निर्मित सामानों में अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि दर्ज हुई। यद्यपि मामूली निर्यात मूल्य की दृष्टि से निर्यातों का हिस्सा (आयातों के विपरीत) कुछ क्षेत्रों में अधिक हो सकता है, तथापि, आयात (निर्यात) घटक भी उच्च ही होगा और इसीलिए योजित मूल्य पर ध्यान देना लाभप्रद होगा (बॉक्स 4.2)।

4.14 भारतीय आयात समूह की एक प्रधान मद पीओएल समूह है, जो 2013-14 में कुल भारतीय आयात का 36.6 प्रतिशत बैठता है। पीओएल के आयात में 2011-12 में 46.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उछाल आया जिसका मुख्य कारण 2010-11 की तुलना में वैश्विक अशोधित तेल की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि रही। पीओएल के आयातों में सामान्य वृद्धि 2012-13 और 2013-14 में क्रमशः 5.9 प्रतिशत और 0.4 प्रतिशत तक रही। अंतर्राष्ट्रीय अशोधित तेल की कीमतें (ब्रेन्ट) 2014-15 की प्रथम तिमाही में

109.8 अमरीकी डालर प्रति बैरल से घटकर तीसरी तिमाही में 76.0 अमरीकी डालर प्रति बैरल रह गई, जिसके परिणामस्वरूप पीओएल आयातों का मूल्य 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में 7.9 प्रतिशत घट गया। पूंजीगत मालों का आयात अन्य प्रधान समूह है जो 2011-12 से लगातार घटता रहा। पूंजीगत मालों के अंतर्गत, मशीनरी के आयातों में 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। भारत के कुल आयातों में स्वर्ण और चांदी आयातों का हिस्सा 2012-13 में 11.4 प्रतिशत और 2013-14 में 7.4 प्रतिशत बैठता है। स्वर्ण और चांदी का आयात 2012-13 एवं 2013-14 में क्रमशः 9.0 प्रतिशत और 40.4 प्रतिशत घट गया, परंतु इनसे 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में 8.0 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। मोतियों, बहुमूल्य और अर्ध मूल्यवान नगों के आयात 2013-14 में 5.4 प्रतिशत बढ़ गए, जबकि 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में 3.9 प्रतिशत घट गए।

व्यापार की दिशा

4.15 हालिया वर्षों में भारत के व्यापार में उल्लेखनीय बाजार विविधीकरण हुआ है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिससे मंद वैश्विक मांग से निपटने की प्रक्रिया में मदद मिली है, जिसका बहुत हद तक कारण यूरो क्षेत्र में दुर्बलता का होना है। यूरोप और अमरीका को भारत के निर्यात का क्षेत्रवार हिस्सा 2004-05 में क्रमशः 23.6 प्रतिशत और 20.1 प्रतिशत से कई वर्षों में घटकर 2013-14 में क्रमशः 18.6 प्रतिशत और 17.2 प्रतिशत रह गया है। इसके विपरीत, एशिया और अफ्रीका में भारत के निर्यातों का हिस्सा 2004-05 में क्रमशः 47.9 प्रतिशत और 6.7 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में क्रमशः 49.4 प्रतिशत और 9.9 प्रतिशत हो गया है। वैश्विक वित्तीय संकट के तुरंत पूर्व और 2010-11 के बाद इस दिशा में हुए परिवर्तन से जाहिर होता है कि विविधीकरण की प्रक्रिया चालू है। संकट से पूर्व (2004-05 से 2007-08) में और संकट के बाद (2010-11 से 2013-14 तक) भारत के व्यापार की तुलना करने से पता चलता है कि भारत का निर्यात और आयात यूरोप, संयुक्त राज्य अमरीका और सिंगापुर से घट गया है, जबकि भारत का व्यापार एशिया और अफ्रीका से बढ़ गया है (सारणी 4.2)।

4.16 2014-15 (अप्रैल-दिसम्बर) में, भारत का निर्यात यूरोपीय क्षेत्र में केवल 0.2 प्रतिशत बढ़ा। तथापि, यूरोपीय देशों में (जिसमें तुर्की, क्रोशिया आदि शामिल हैं) भारत का निर्यात 2014-15 (अप्रैल-दिसम्बर) में लगभग 38.1 प्रतिशत बढ़ा। अफ्रीका और अमरीका में 2014-15 में भारत का निर्यात (अप्रैल-दिसम्बर) क्रमशः 12.9 और 14.5 प्रतिशत

बाक्स 4.2 : भारतीय निर्यातों में योजित घरेलू मूल्य के श्रम एवं श्रमेतर घटकों के अनुमान

व्यापार की बदल रही रूपरेखाओं और वैश्विक उत्पादन शृंखलाओं के आविर्भाव के विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ होते हैं। आयातित वस्तुओं के बढ़ते उपयोग के कारण कुल निर्यातों के घरेलू मूल्य योजित हिस्से में सामान्यतया गिरावट आती है। पूंजी और विभिन्न प्रकार के श्रम से योजित मूल्य का अपघटन (डीकंपोजीशन) उत्पादन प्रक्रिया के वैश्विक विखंडन का महत्वपूर्ण पहलू है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि व्यापार के बढ़ने और इसके परिणामतः विश्व बाजार एकीकृत होने से विकासशील देशों के मध्यम और अल्प कुशलता प्राप्त अपने अधिकांश श्रमिकों को नियोजित करने के नए अवसर मिलेंगे। घरेलू योजित मूल्य के उपर्युक्त अपघटन इस बात की जांच करने की अनुमति देते हैं कि वैश्वीकरण के लाभ पूंजी और विभिन्न प्रकार के श्रमिकों के बीच किस तरह बांट दिए जाते हैं।

भारतीय संदर्भ में, कुल निर्यातों में घरेलू योजित मूल्य के निर्यातों का हिस्सा 1998-99 में 86.9 प्रतिशत से गिरकर 2003-04 में 84.1 प्रतिशत और 2007-08 में और गिरकर 78.5 प्रतिशत तक रह गया है। किन्तु आयातों में विदेशी योजित मूल्य का हिस्सा बढ़ गया, जो अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन के विखंडन की प्रक्रिया के गहनता का संकेत है। घरेलू श्रम घटक, भारतीय सेवा निर्यातों में व्यापारिक माल निर्यातों से अपेक्षाकृत उच्च है। इसके अलावा, चार घटकों (अकुशल, अर्धकुशल, कुशल श्रमिकों और श्रमेतर के आधार पर निर्यातों का घरेलू मूल्य यह दर्शाता है कि कुशलता प्राप्त श्रमिक एवं श्रमेतर घटकों का सम्मिलित हिस्सा अत्यधिक उच्च है जिससे कुशल श्रम और पूंजी के उपयोग की और तरफदारी करने वाली प्रौद्योगिकी में व्यापक परिवर्तन किये जाने का संकेत मिलता है। घटक वस्तुओं के अनुसार भारतीय निर्यातों के घरेलू मूल्य के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि व्यापारिक माल निर्यातों के लिए योजित घरेलू मूल्य में श्रम घटक 2007 में 28 प्रतिशत था जबकि यह कुल निर्यातों (सेवा सहित) के मामले में उसी वर्ष 39 प्रतिशत था। सेवा निर्यातों के लिए, तदनु रूप आंकड़े लगभग 51 प्रतिशत हैं जिससे यह संकेत मिलता है कि घरेलू श्रम घटक, व्यापारिक माल निर्यातों की अपेक्षा सेवा निर्यातों में उच्च है। घरेलू मूल्य योजन (सारणी 1) में श्रमिकों का योगदान 1998-99 से 2007-08 तक की अवधि के दौरान व्यापारिक माल निर्यातों में घट गया है (6 प्रतिशतांक से अधिक) और सेवा निर्यातों में (2 प्रतिशतांक तक) बढ़ गया है। विखंडित स्तर पर भारत के योजित घरेलू मूल्य निर्यात में श्रम घटक का अनुपात मुख्यतः कृषि खाद्य प्रसंस्करण और सेवा क्षेत्रों में बढ़ गया है; जबकि पूंजीगत अंशदान मशीनरी, धात्विक उत्पादों एवं अन्य अनेक विनिर्माण क्षेत्रों में बढ़ गया है।

सारणी 1 : घरेलू मूल्य योजित निर्माताओं का 1998-99 से 2007-08 तक कारक घटकों में अपसंघटन

(प्रतिशत प्रतिवर्ष)

क्षेत्र	श्रम घटक			श्रमेतर घटक			योजित घरेलू मूल्य		
	1998-99	2003-04	2007-08	1998-99	2003-04	2007-08	1998-99	2003-04	2007-08
व्यापारिक माल निर्यात	34.2	32.1	27.9	50.7	47.3	42.9	85.0	79.4	70.8
सेवा निर्यात	48.8	51.4	50.9	42.0	41.4	35.8	90.8	92.8	86.7
कुल निर्यात	39.2	38.9	39.1	47.8	45.2	39.5	86.9	84.1	78.5

टिप्पणी : डीवीए के श्रम और श्रमेतर घटक 100 तक नहीं जोड़े जाते क्योंकि शेष भाग विदेशी योजित मूल्य घटक है।

स्रोत : यह संगणना, सीएसओ, एएसआई, एनएसएस सर्वेक्षण चक्रों और सामाजिक लेखांकन मेट्राइस द्वारा प्रकाशित इनपुट आउटपुट सारणियों पर आधारित है

श्रमिकों के कौशल के स्तर के अनुसार कारक घटकों का वितरण नीचे सारणी 2 में दर्शाया गया है। समग्र स्तर के अनुमानों से पता चलता है कि विनिर्माताओं के लिए अकुशल श्रम और पूंजी घटक का हिस्सा उच्च है जबकि सेवा निर्यातों एवं कुल निर्यातों में पूंजी तथा उच्च कुशल श्रमिकों का हिस्सा मध्यम, कुशल और अकुशल श्रमिकों के हिस्से से अत्यधिक उच्चतर है।

सारणी 2: घटक वस्तु और कुशल श्रम के स्तर 2007 के अनुसार भारत के निर्यातों के घरेलू मूल्य का वितरण (प्रतिशत में)

क्षेत्र	अकुशल श्रम घटक	अर्द्धकुशल श्रम घटक	कुशल श्रम घटक	श्रमेतर घटक	विदेशी मूल्य योजित हिस्सा
व्यापारिक माल निर्यात	10.9	8.8	8.0	43.1	29.2
<i>निर्यात की शीर्ष मदें</i>					
1. पेट्रोलियम उत्पाद	2.0	2.2	2.4	27.6	65.8
2. तैयार वस्त्र	17.3	13.7	9.8	42.7	16.4
3. रत्न एवं आभूषण	10.0	10.3	7.8	35.2	36.6
4. औषध एवं दवाइयां	8.7	8.0	9.6	47.6	26.1
सेवा निर्यात	10.3	14.5	26.1	35.9	13.3
कुल निर्यात	10.6	11.6	16.8	39.6	21.5

स्रोत : यह संगणना, सीएसओ, एएसआई, एनएसएस सर्वेक्षण चक्रों और सामाजिक लेखांकन मेट्राइस द्वारा प्रकाशित इनपुट आउटपुट सारणियों पर आधारित है

अनेक अन्य उभरते देशों के मामले में कारक घटकों में यही पैटर्न देखा गया है कि जहां पूंजी और उच्च कुशल श्रम के हिस्से बढ़ चुकने का निहितार्थ यह है कि वैश्विक मूल्य शृंखलाओं से पूंजी और श्रम की प्रधानता बढ़ती जा रही है।

स्रोत : आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 'एस्टीमेटिंग डॉमिस्टिक वेल्यू एडड एण्ड फॉरेन कान्टेन्ट आफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स' पर देव कुसूमदास, श्री रूप सेन गुप्ता और पीलू चन्द्र दास द्वारा कृत अध्ययन पर आधारित।

सारणी 4.2 : भारतीय व्यापार में क्षेत्रों/देशों का निर्यात और आयात हिस्सा

क्षेत्र/ देश	निर्यात			आयात			आयात के अनुपात में निर्यात		
	2004-05 से 2007-08	2010-11 से 2013-14	हिस्से में परिवर्तन	2004-05 से 2007-08	2010-11 से 2013-14	हिस्से में परिवर्तन	2004-05 से 2007-08	2010-11 से 2013-14	हिस्से में
यूरोप	23.3	19.0	-4.3	21.6	18.0	-3.6	73.6	68.6	-5.0
जर्मनी	3.3	2.5	-0.7	3.9	3.0	-0.9	56.5	53.9	-2.5
बेल्जियम	2.7	2.1	-0.6	2.6	2.2	-0.3	73.4	62.4	-10.9
स्वीट्जरलैंड	0.4	0.4	0.0	4.5	6.2	1.7	6.7	4.2	-2.5
अफ्रीका	7.8	8.9	1.2	6.3	8.5	2.2	84.0	68.1	-15.9
नाइजरिया	0.7	0.9	0.1	2.1	2.9	0.8	23.8	19.7	-4.1
अमरीका	18.9	16.6	-2.3	10.3	11.0	0.7	124.9	98.3	-26.6
यूएसए	14.9	11.6	-3.3	7.1	5.1	-2.0	143.5	148.5	5.0
एशिया	48.5	50.2	1.7	48.9	60.2	11.3	67.7	54.4	-13.4
सिंगापुर	4.8	4.5	-0.3	2.8	1.7	-1.2	116.6	177.7	61.1
इंडोनेशियन	1.5	1.9	0.5	2.1	3.0	0.9	47.2	41.5	-5.8
यूनाइटेड अरब अमीरात	9.2	11.7	2.5	4.5	7.6	3.2	140.0	99.2	-40.8
साउदी अरब	2.0	2.8	0.8	5.1	6.8	1.7	26.6	26.3	-0.3
कुवैत	0.5	0.4	0.0	2.1	3.4	1.3	15.4	8.5	-6.9
कतर	0.3	0.2	0.0	0.9	2.8	2.0	22.0	5.6	-16.4
इराक	0.2	0.3	0.2	1.8	3.6	1.9	6.2	5.5	-0.6
चीन	6.6	5.3	-1.3	9.0	11.2	2.2	50.4	30.8	-19.6
हांगकांग	4.0	4.1	0.1	1.3	1.9	0.6	210.1	137.7	-72.5
कोरिया	1.7	1.4	-0.3	2.7	2.7	0.0	43.6	33.8	-9.8
कुल	100.0	100.0	—	100.0	100.0	—	68.2	65.1	-3.1

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े पर आधारित संगणना।

बढ़ा एशिया, जो भारत के निर्यातों (जो लगभग 50 प्रतिशत बैठता है) का प्रधान गंतव्य है, ने 2014-15 (अप्रैल-दिसम्बर) में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। एशिया के अंदर भारत का दक्षिण एशिया में निर्यात 23.8 प्रतिशत बढ़ गया (श्रीलंका, नेपाल और बांग्ला देश में निर्यात की उच्च वृद्धि के मुख्य कारण से) और यह निर्यात पश्चिम एशिया खाड़ी सहयोग परिषद् (यूईई, सउदी अरब और अन्य आदि) के मामले में 8.8 प्रतिशत बढ़ा। एशिया के दूसरे क्षेत्रों में भारत के निर्यात में 2014-15 (अप्रैल-दिसम्बर) में कमी दिखाई दी। उत्तर पूर्व एशिया (चीन, हांगकांग, जापान सहित) में 4.4 प्रतिशत की, एशियन (सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाइलैंड, मलेशिया आदि) में 7.2 प्रतिशत की और अन्य पश्चिम एशिया (ईरान, इजरायल और अन्य) में 8.5 प्रतिशत की गिरावट थी। देशवार यूएसए और यूईई भारत के निर्यातों (2013-14 में कुल निर्यातों में 12.5 प्रतिशत, 9.7 प्रतिशत के हिस्से के साथ) के प्रधान गंतव्य है। इनका निर्यात 2014-15 (अप्रैल-दिसम्बर) में 11.2 प्रतिशत और 11.9 प्रतिशत बढ़ा। किंतु इसी अवधि

में चीन (4.7 प्रतिशत हिस्सा) और बेल्जियम (2.0 प्रतिशत) के लिए भारत का निर्यात 14.7 प्रतिशत और 10.7 प्रतिशत घट गया। 2012-13 से, सिंगापुर और इंडोनेशिया के लिए भारतीय निर्यातों में कमी रही है।

4.17 भारतीय आयातों में यूरोप का हिस्सा 2004-05 में 23.0 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 15.8 प्रतिशत रह गया जबकि एशिया और अफ्रीका का हिस्सा 2004-05 में 35.6 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत से पर्याप्त रूप से बढ़कर 2013-14 में क्रमशः 60.7 प्रतिशत और 8.1 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में भारतीय आयातों में अमरीकी हिस्सा 8.8 प्रतिशत से बढ़कर 12.8 प्रतिशत हो गया। चीन भारतीय आयातों का प्रधान स्रोत है। जिससे 2013-14 में किया गया आयात कुल भारतीय आयातों का 11.3 प्रतिशत बैठता है। इसके बाद सउदी अरब (8.1 प्रतिशत हिस्सा यूईई (6.5 प्रतिशत हिस्सा) और यूएसए (5.0 प्रतिशत हिस्सा), का स्थान है। 2014-15 (अप्रैल-दिसम्बर) में, चीन से

भारतीय आयात 18.7 प्रतिशत तक बढ़ गया। किंतु इसी अवधि में सऊदी अरब, यूएई और अमरीका से भारतीय आयातों में क्रमशः 14.2 प्रतिशत, 7.9 प्रतिशत और 7.9 प्रतिशत की कमी आई। स्वित्जरलैंड और सिंगापुर से किए गए आयात भी 2012-13 और 2013-14 में घट गए, किंतु 2014-15 (अप्रैल-दिसम्बर) में सकारात्मक वृद्धि से बढ़ गए।

व्यापार घाटा

4.18 2013-14 में, भारत का व्यापार घाटा (सीमा-शुल्क आधार पर) आयातों की वृद्धि में गिरावट (8.3 प्रतिशत) के मुख्य कारण से 2012-13 में 190.3 बिलियन अमरीकी डालर के उच्च स्तर से घटकर 135.8 बिलियन अमरीकी डालर रह गया, यद्यपि निर्यातों में वृद्धि 4.7 प्रतिशत पर मंद गति से हुई। आयातों में गिरावट का कारण तेल आयातों में अल्प वृद्धि (0.4 प्रतिशत) तथा स्वर्ण और चांदी आयातों में नकारात्मक वृद्धि रही। तथापि, 2013-14 (अप्रैल-जनवरी) में व्यापार घाटा 116.5 बिलियन अमरीकी डालर के विपरीत 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में मामूली रूप से 1.6 प्रतिशत बढ़कर 118.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। अल्प निर्यात वृद्धि (2.4 प्रतिशत) और आयातों में उछाल (2.2 प्रतिशत) के परिणामस्वरूप व्यापार घाटे में 1.8 बिलियन अमरीकी डालर की सीमित वृद्धि हुई। इसके बावजूद, स्तरों की दृष्टि से व्यापार घाटा जो विगत वर्ष के नजदीक है, व्यापार नीतियों सहित विदेशी क्षेत्रक नीतियों का ही प्रतिफल है।

व्यापार नीति

व्यापार संबंधी नीतिगत उपाय

4.19 2011-12 से वैश्विक और घरेलू कारकों के चलते उत्पन्न व्यापार घाटे के उच्च स्तर जो 2013-14 की प्रथम तिमाही में बना रहा, के परिणामस्वरूप विदेशी क्षेत्र के परिणाम पर गंभीर दबाव पड़ा जिसके विशाल वृहत आर्थिक निहितार्थ हुए। सरकार ने निर्यात क्षेत्रों के निष्पादन के संवर्धन के लक्ष्य वाले उपायों सहित विभिन्न प्रकार के उपाय किए जो बजट उद्घोषणाओं और विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) 2009 तथा इसके वार्षिक अनुपूर्कों के पूरक थे। विभिन्न योजनाएं सुदृढ़ की गयीं; जैसे, कि उत्पाद केंद्रित योजना (एफपीएस), बाजार केंद्रित योजना (एफएमएस), बाजार संबद्ध उत्पाद केंद्रित योजना (एमएलएफपीएस) और विशेष कृषि तथा ग्रामोद्योग योजना (वीकेजीयूवाई)। इसके अलावा,

उद्योग और व्यापार निकायों को बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम और बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम के अंतर्गत विभिन्न देशों में क्रैता विक्रेता बैठकों (बीएसएम), व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सहायता दी जाती है।

4.20 सरकार द्वारा किए गए कुछ हालिया उपाय बाक्स 4.3 में दिए गए हैं।

डंपिंग रोधी उपाय

4.21 देश के घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करने के विचार से, बड़े बाजारों द्वारा डंपिंग रोधी कार्रवाई का सहारा लिया जा रहा है ताकि वे उन विदेशी निर्यातकों से घरेलू बाजार में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम हो सकें जिनमें से कुछ डंपिंग का सहारा लेते हों। एंटी डंपिंग और संबद्ध ड्यूटी महानिदेशालय (डीजीएडी) देश में माल की डंपिंग के प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के साथ घरेलू उद्योग द्वारा दर्ज कराए गए आवेदनों, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा डंपिंग और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारण कार्य संबंध के आधार पर डंपिंग रोधी जांच करता है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई इन याचिकाओं पर सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और इसके अंतर्गत बनी नियमावली के तहत विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार और नियत समय सीमा के भीतर कार्यवाही की जाती है। डीजीएडी जांच संचालित करता है और, जहां उचित हो, अपने प्रारंभिक/अंतिम परिणाम जारी करते हुए राजस्व विभाग को शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। डीजीएडी की इन सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए, राजस्व विभाग अनंतिम या स्थायी शुल्क लगा सकता है।

4.22 डंपिंग रोधी जांचें अन्य देशों द्वारा भी प्रारंभ की गई हैं और वर्ष 2013 में कुल लगभग 287 जांचें प्रारंभ की गई थी (सारणी 4.3)। वर्ष 2012 में ब्राजील ने भारत को पीछे छोड़ते हुए भारत की तुलना में दोगुनी जांचें प्रारंभ कीं। वर्ष 2013 में भी ब्राजील की जांचें सर्वाधिक 54 थीं। इसके बाद अमरीका और भारत का स्थान था। वर्ष 2014 में जून के अंत तक भारत और अमरीका दोनों ने बराबर संख्या में जांचें आरंभ की हैं। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार भारत द्वारा आरंभ 690 मामलों में से 533 में शुल्क लगा दिए गए हैं; चीन ने कुल आयातों को अधिकतम संख्या में जांचों का सामना किया और 166 मामलों में से 134 में शुल्क लगाया गया।

बाक्स 4.3 : व्यापार नीति संबंधी किए गए कुछ हालिया उपाय

- घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं नामतः एफपीएस, एफएमएस, वीकेजीयूवाई, एमएलएफपीएस, सर्वड फ्राम इंडिया स्कीम (एसएफआईएस), कृषि अवसंरचना प्रोत्साहन स्कीम (एआईआईएस) के अंतर्गत मालों के आयात के लिए जारी स्क्रिप्सों का उपयोग घरेलू खरीद के लिए उत्पाद शुल्क के भुगतान हेतु किया जा सकता है। यह आयात प्रतिस्थापन का महत्वपूर्ण उपाय है और इससे रोजगार सृजन के अलावा विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलेगी।
- इसी प्रकार, एफपीएस, एफएमएस, विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना स्कीम के तहत जारी स्क्रिप्सों का उपयोग सेवा कर के भुगतान के लिए किया जा सकता है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) से उत्पादों के निर्यात में सहयोग देने के लिए, निर्यातक एफटीपी के तहत अन्य लाभों के अलावा निर्यातों के एफओबी मूल्य के एक प्रतिशत के अतिरिक्त प्रोत्साहन के हकदार है यदि निर्यात एनईआर में अवस्थित थल सीमा शुल्क केंद्र से किए जाएं।
- भारत के निर्यातों को विविधीकृत करने के लिए, 7 नए बाजार (अलजीरिया, अरूबा, आस्ट्रिया, कंबोडिया, म्यांमार, नीदरलैंड, एन्टिलिस और यूक्रेन) एफएमएस से जोड़ दिए गए हैं, 7 नए बाजार (बिलिज, चिली, एल सलवाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरस, मोरक्को और उरूग्वे) (स्पेशल एफएमएस) में जोड़ दिए गए हैं, 46 नई मर्दे बाजार संबद्ध उत्पाद केंद्रित स्कीम से जोड़ी गयी है जिनमें उत्पाद केंद्रित स्कीम की सूची में 12 नए बाजार पहली बार और 100 नई मर्दे भी जोड़ी गई हैं।
- सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने अभिज्ञात सेवा क्षेत्रों में सेवा कान्क्लेव के दो संस्करण संगठित किए हैं जो भारत के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इस कान्क्लेव में, विशिष्ट सेवा क्षेत्रों की बाधाओं, यदि कोई हो, की पहचान की जाती है और आवश्यक सुधारों से संबंधित मुद्दों, उन क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के लिए भारत की संभाव्यता और निर्यातक सेवाओं के लिए नए बाजारों इत्यादि पर चर्चा की जाती है। अप्रैल, 2015 में नई दिल्ली में एक वैश्विक सेवा प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जो सेवा क्षेत्र के प्रतिस्पर्द्धियों और उनके वैश्विक प्रति स्थानियों के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने तथा सामंजस्य विकसित करने के लिए प्लेटफॉर्म का कार्य करेगी।
- भारतीय ट्रेड पोर्टल (www.indiantradeportal.in) को 8 दिसंबर, 2014 को प्रारंभ किया गया था। यह पोर्टल भारतीय उद्योग को लगभग 42 निर्यात बाजारों पर महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है और विभिन्न क्षेत्रीय और द्विपक्षीय निःशुल्क व्यापार करारों और व्यापक आर्थिक सहयोग/साझेदारी करारों के माध्यम से प्रदत्त बढ़ी हुई बाजार अभिगम्यता का लाभ उठाने के लिए तंत्र भी उपलब्ध कराता है। इस सूचना पोर्टल में जाने के लिए निर्यातकों और आयातकों को 4 आसान चरणों में प्रयोक्ता अनुकूल तरीके से सूचना प्रदान की जाती है, जो व्यापार और उद्योग के लिए व्यवसाय करने की सुगमता में सहयोग प्रदान करेगी। यह पोर्टल निर्यातकों और आयातकों के उपयोग के लिए एक ही स्थान पर उन देशों से संबंधित (प) एमएफएन प्रशुल्क, (पप) तरजीही प्रशुल्क, (पपप) उत्पत्ति नियमावली (आरओओ) और गैर-प्रशुल्क उपाय जैसे महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करता है, जिनके साथ हमारे विदेशी व्यापार करार (एफटीए) हैं। इसके फलस्वरूप, यह भारत के निर्यातों के लिए सुकर है और यह एफटीए का उपयोग करने में निर्यातकों की मदद करेगा और विभिन्न देशों में उन्हें प्रदान किए गए तरजीही प्रशुल्कों तक पहुंच के लिए भी सहायता प्रदान करता है ताकि वे निर्यात अवसरों का लाभ उठा सकें।
- राज्यों को मुख्य धारा में लाने के लिए, ताकि वे निर्यातों को बढ़ावा देने पर स्पष्ट रूप से बल दे सकें राज्यों द्वारा अपेक्षित रूप से आरंभ किए जाने वाले महत्वपूर्ण अवयवों/उपायों को त्रुटि रहित और सूचीबद्ध किया गया है। निम्नलिखित को शामिल करने के लिए एक 15 सूची कार्यक्रम तैयार किया गया है और इसे सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को भेज दिया गया है: (क) राज्य सरकार द्वारा निर्यात रणनीति का विकास, (ख) राज्य सरकारों द्वारा केंद्र के साथ किए गए सभी निर्यात संबंधी क्रियाकलापों के समन्वय के लिए एक निर्यात आयुक्त की नियुक्ति, और (ग) राज्यों के अग्रणी निर्यातकों को प्रेरित करने के लिए निर्यात पुरस्कारों की स्थापना करना और उन्हें और अधिक निर्यात राजस्व अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) वार्ताएं और भारत

4.23 हालांकि उपर्युक्त उपाय उभरते वैश्विक क्षेत्र के वातावरण के प्रति मोटे तौर पर घरेलू नीति का समायोजन थे लेकिन भारत डब्ल्यूटीओ वार्ताओं में शामिल होता रहा। इनका समग्र अर्थव्यवस्था के साथ-साथ वैदेशिक क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। डब्ल्यूटीओ का नौवां मंत्रालयी सम्मेलन बाली में दिसंबर 3-7, 2013 के दौरान आयोजित किया गया। मंत्रियों ने व्यापार सुगमीकरण, पर एक घोषणा और दस निर्णय जारी किए और कृषिगत व्यापार नियमावली विकास तथा अल्प

विकसित देशों (एलडीसी) से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। इन निर्णयों में, दो मंत्रालयी निर्णय अर्थात् व्यापार सुगमीकरण पर करार के लिए मंत्रालयी निर्णय और खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सरकारी स्टॉकधारिता पर मंत्रालयी निर्णय भारत के लिए विशेष महत्व के हैं।

4.24 व्यापार सुगमीकरण करार (टीएफए), जिसका नौवें मंत्रालयी सम्मेलन में भारत द्वारा भी समर्थन किया गया था, का बुनियादी रूप से सीमा-शुल्क पद्धतियों की बेहतर पारदर्शिता और सरलीकरण, इलैक्ट्रॉनिक भुगतानों और जोखिम प्रबंधन तकनीकों के प्रयोग और बंदरगाहों पर तीव्र निकासी पर

सारणी 4.3: डंपिंग रोधी उपायों के शीर्ष दस प्रयोक्ताओं द्वारा प्रारंभ की गई जांचें

देश	2001	2011	2012	2013	जन.-जून	
					2013	2014
भारत	79	19	21	29	17	13
संयुक्त राज्य	77	15	11	39	7	13
यूरोपीय संघ	28	17	13	4	3	3
ब्राजील	17	16	47	54	17	29
अजेन्टिना	28	7	12	19	12	4
आस्ट्रेलिया	24	18	12	20	5	11
दक्षिण अफ्रीका	6	4	1	10	5	1
चीन	14	5	9	11	8	4
कनाडा	25	2	11	17	10	3
तुर्की	15	2	14	6	4	2
सभी देश	372	165	208	287	122	106

स्रोत : विश्व व्यापार संगठन

लक्ष्य रखा गया है। व्यापार सुगमीकरण को प्रमुखतः विकसित देशों द्वारा कार्य सूची में लाया गया था। खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सरकारी स्टॉक धारिता से संबंधित नियमावली के मुद्दे को भारत के प्रयासों के माध्यम से कार्य सूची में शामिल किया गया था।

4.25 डब्ल्यूटीओ के कृषि संबंधी करार में कृषिगत व्यापार नियमावली, खाद्य सुरक्षा के लिए सरकारी स्टॉक धारिता कार्यक्रमों को बाधित नहीं करती। तथापि, यदि ऐसे कार्यक्रमों के लिए बाजार कीमतों के स्थान पर निर्धारित कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त किया जाता है, तो इसे किसानों के लिए सहायता के रूप में माना जाता है। उरूग्वे दौर में चर्चित डब्ल्यूटीओ नियमावली के अनुसार, ऐसी सारी सहायता को विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के मूल्य की 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर रखा जाता है। यह उच्चतम सीमा विकासशील देशों में प्रापण और खाद्य सहायता कार्यक्रमों को निरुद्ध कर सकती है। विकसित देशों के हितों को सर्वोच्च रखते हुए बनी डब्ल्यूटीओ नियमावली में विकासशील देशों के हितों की अनदेखी की गई है। दिसंबर 2008 के कृषि वार्ता पाठ के मसौदे में इसे बदलने की मांग की गई है। इसमें नियमावली को संशोधित करने का प्रस्ताव निहित है, परंतु चूंकि वार्ताओं का निष्कर्ष नहीं निकला है, इसलिए यह एक अपूर्ण कार्य सूची रह गई है। 'जी-33' नामक विकासशील देशों के संघ के हिस्से के रूप में भारत ने इन नियमों को बदलने के लिए डब्ल्यूटीओ के कृषि संबंधी करार में संशोधन का प्रस्ताव किया।

4.26 जी-33 प्रस्तावों और साथ ही इस समूह द्वारा सुझाए गए विभिन्न विकल्पों को विरोध का सामना करना पड़ा। बाली मंत्रालययी सम्मेलन के दौरान भी वार्ताएं जारी रहीं। मंत्रालयी निर्णय के अंतिम रूप से सहमति प्राप्त पाठ में सदस्यों के लिए एक अंतरिम तंत्र स्थापित करने और डब्ल्यूटीओ के 11वें मंत्रालयी सम्मेलन द्वारा अंगीकृत करने के लिए एक स्थायी समाधान हेतु करार पर वार्ता करने का प्रावधान किया गया है। जब तक स्थायी समाधान नहीं निकलता तब तक अंतरिम समाधान में, कतिपय शर्तों के अधधीन सदस्यों को खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सरकारी स्टॉक धारिता कार्यक्रमों के संबंध में कृषि संबंधी करार के तहत डब्ल्यूटीओ की चुनौती के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गई थी। विकसित देशों का विशेष ध्यान व्यापार सुगमीकरण करार के क्रियान्वयन पर ही रहा। इस असमान प्रगति से चिंतित भारत ने जुलाई 2014 में यह रूख अपनाया कि अन्य बाली निर्णयों पर परिणामों की दृढ़ प्रतिबद्धता के बिना, व्यापार सुगमीकरण करार (टीएफए) को डब्ल्यूटीओ करार के छत्र में शामिल करने के लिए संशोधन के प्रोटोकॉल पर सर्वसम्मति से भारत का सम्मिलित होना कठिन होगा।

4.27 टीएफए की अंतिम तिथि चूकने के बारे में आई मिथ्या सूचना की आम मुहिम और डब्ल्यूटीओ के भविष्य पर गतिरोध के प्रभाव के बावजूद, भारत दृढ़ रहा। अपनाए गए दृष्टिकोण के मूल में अंतर्निहित सरोकारों को स्पष्ट करने के लिए संयुक्त प्रयास किए गए और भारत ने आगे का रास्ता निकालने के लिए डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्यों के साथ कार्य

किया। 27 नवंबर, 2014 को डब्ल्यूटीओ की महापरिषद (जनरल काउंसिल) ने खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉक संचय पर निर्णय, व्यापार सुगमीकरण करार पर निर्णय और बाली के कार्य के पश्चात् (पोस्ट बाली वर्क) निर्णय को अपनाया। महापरिषद के खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सरकारी स्टॉक धारिता संबंधी निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसा तंत्र, जिसके तहत डब्ल्यूटीओ सदस्य विकासशील सदस्य देशों के खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों हेतु सरकारी स्टॉक धारिता कार्यक्रमों को चुनौती नहीं देंगे, कृषि संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अधीन कतिपय दायित्वों के संबंध में तब तक स्थायित्व में बना रहेगा जब तक कि इस मुद्दे के संबंध में कोई स्थायी समाधान स्वीकृत और अंगीकृत नहीं हो जाता। इसमें सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर 31 दिसंबर, 2015 तक खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉक धारिता पर स्थायी समाधान निकालने की प्रतिबद्धता भी शामिल है और इस कार्य के एक त्वरित कार्यक्रम के माध्यम से एक स्थायी समाधान संबंधी बातचीत में शामिल होने की भी दृढ़ प्रतिबद्धता है। इस निर्णय में खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सरकारी स्टॉक धारिता के मुद्दे पर भारत के सरोकारों का समाधान है। डब्ल्यूटीओ (एमसी10) का दसवां मंत्रालयी सम्मेलन 15 से 18 दिसंबर 2015 के दौरान नैरोबी, कीनिया में आयोजित किया जाएगा।

भुगतान संतुलन संबंधी गतिविधियां

भुगतान संतुलन का सिंहावलोकन

4.28 वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, वित्तीय संकट के प्रति नीति अनुक्रियाओं के समन्वय पर जी-20 के प्रयासों के बावजूद, ईएमडीई को विकसित अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों और वित्तीय चैनलों के माध्यम से उत्पन्न होने वाले आवर्ती आघातों या दबावों का सामना करना पड़ा था। भारतीय अर्थव्यवस्था को भी इन आघातों को झेलना पड़ा था। ये आघात कमजोर वैदेशिक मांग और कच्चे तेल के आयातों, जिनकी कीमतों का स्तर चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही तक ऊंचा बना हुआ था, पर अत्यधिक निर्भरता के चलते अपेक्षाकृत सुदृढ़ घरेलू मांग के मिले-जुले प्रभाव के कारण और भी अधिक बढ़ गए थे। इन आघातों के परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 में चालू खाता घाटा और बढ़ गया था जो वर्ष 2013-14 की प्रथम तिमाही तक बना रहा। वैदेशिक वित्तपोषण के स्रोत के अस्थिर रहने, इनके पर्याप्त मात्रा से कम रहने और उनकी घटती गुणवत्ता के कारण रुपये के मूल्य में तीव्र गिरावट आई। वर्ष 2013-14 में की गई

नीतिगत अनुक्रियाओं से चालू खाता घाटा (सीएडी) के स्तरों में गिरावट के माध्यम से इस दबाव पर काबू पाने में मदद मिली और इसके तथा प्रचुर वित्तपोषण के परिणामस्वरूप आरक्षित मुद्रा भंडारों में अनुवृद्धि हुई जिससे लोचशीलता बनाए रखने में मदद मिली और यह प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष तक बनी रही।

4.29 वर्ष 2014-15 के पूर्वार्द्ध में, भारत के वैदेशिक क्षेत्र की स्थिति हितकर और आरामदायक रही (सारणी 4.4)। दो महत्वपूर्ण गतिविधियां (i) अदृश्य आयातों निर्यातों में सामान्य वृद्धि के साथ निम्न व्यापार घाटे के परिणामस्वरूप निम्न चालू खाता घाटा और (ii) उच्च पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और वैदेशिक वाणिज्यिक ऋण से समर्थ हुई पूंजी आवकों में अत्यधिक वृद्धि रही। उच्चतर पूंजी अंतर्वाह, वित्तपोषण की आवश्यकता या चालू खाता घाटा से अधिक थे और इनकी परिणति विदेशी मुद्रा भंडार में अभिवृद्धि के रूप में हुई। व्यापारिक माल व्यापार के संबंध में उपलब्ध प्रथम छमाही के बाद के आंकड़े जिन पर पूर्व के खंड में चर्चा की गई थी, यह दर्शाते हैं कि व्यापार घाटा मोटे तौर पर अपेक्षाकृत सामान्य स्तर पर बना रहा और वित्तीय अंतर्वाहों तथा विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित उपलब्ध मासिक आंकड़े सुस्पष्ट ढंग से आरक्षित अनुवृद्धि को इंगित करते हैं और वैदेशिक वित्तपोषण की प्रचुर मात्रा की ओर संकेत करते हैं। सामान्य व्यापार के परिणाम का एक कारण अशोधित पेट्रोलियम की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई वर्तमान गिरावट है। उपर्युक्त घटनाक्रमों को देखते हुए और वर्तमान अनुमान को समयोचित मानते हुए, सरकार ने 19 अक्टूबर, 2014 को हार्ड स्पीड डीजल की कीमतों पर से अपना नियंत्रण हटा लिया और 29 नवम्बर 2014 को सोने के आयात पर लगे हुए प्रतिबंध हटा लिए।

वर्ष 2014-15 में (अप्रैल-सितम्बर) में चालू खाता संबंधी गतिविधियां

4.30 भुगतान संतुलन (बीओपी) संबंधी आंकड़े, जो लगभग एक तिमाही पश्चात उपलब्ध हुए हैं, यह संकेत करते हैं कि वर्ष 2014-15 के पूर्वार्द्ध में आयातों में निम्न वृद्धि के परिणामस्वरूप व्यापार संतुलन खाते (भुगतान संतुलन के आधार पर) में वर्ष दर वर्ष सुधार हुआ जिससे व्यापारिक माल निर्यात वृद्धि में नरमी को दूर करने में सफलता मिली। वर्ष 2014-15 (अप्रैल-सितम्बर) में व्यापारिक माल निर्यात 7.6% बढ़कर 167.0 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया। तथापि, दूसरी तिमाही में, तेल की कीमतों में नरमी के कारण निर्यात वृद्धि में कुछ गिरावट वर्ष 2013-14 (दूसरी

सारणी 4.4 : भुगतान संतुलन : सार		(मिलियन अमरीकी डालर)						
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (आ.सं)	2013-14 (अ)	2013-14 पूर्वार्ध (अप्रैल-सितं 2013(अ))	2014-15 पूर्वार्ध (अप्रैल-सितं 2014(अ))
I	चालू खाता							
	1. निर्यात	182442	256159	309774	306581	318607	155152	166974
	2. आयात	300644	383481	499533	502237	466216	238941	240188
	3. व्यापार संतुलन	-118202	-127322	-189759	-195656	-147609	-83789	-73214
	4. अदृश्य आयात-निर्यात (निवल)	80022	79269	111604	107493	115212	56830	55272
	क. सेवाएं	36016	44081	64098	64915	72965	35239	36069
	ख. अंतरण	52045	53140	63494	64034	65276	32744	32757
	ग. आय	-8038	-17952	-15988	-21455	-23028	-11153	-13554
		-38181	-48053	-78155	-88163	-32397	-26959	-17942
II	चालू खाता शेष							
	i. बाह्य सहायता	2890	4941	2296	982	1032	130	606
	ii. बाह्य वाणिज्यिक उधार	2000	12160	10344	8485	11777	2455	3429
	iii. अल्पावधि ऋण	7558	12034	6668	21657	-5044	589	69
	iv. बैंकिंग पूंजी	2083	4962	16226	16570	25449	11487	-542
	जिसकी अनिवासी							
	जमा	2922	3238	11918	14842	38892	13700	6473
	v. विदेशी निवेश	50362	42127	39231	46710	26386	7762	38385
	क. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	17966	11834	22061	19819	21564	14589	16183
	ख. पोर्टफोलियो निवेश	32396	30293	17170	26891	4822	-6827	22202
	vi. अन्य प्रवाह	-13259	-12484	-7008	-5105	-10813	-6619	-3407
	पूंजी खाता शेष	51634	63740	67755	89300	48787	15806	38539
III	भूल-चूक	-12	-2636	-2432	2689	-882	453	-2522
	पूंजी खाता (भूल-चूक सहित)	51622	61104	65323	91989	47905	16259	36017
IV	समग्र शेष	13441	13050	-12831	3826	15508	-10701	18076
V	आरक्षित निधि परिवर्तन	-13441	-13050	12831	-3826	-15508	10701	-18076
	(-) बढ़त को दर्शाता है, (+) घटत को दर्शाता है							

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

टिप्पणी : पी.आर.: आंशिक संशोधन पी: अनंतिम

तिमाही) में औसत 105.1 अमरीकी डॉलर प्रति बी.बी.एल. से गिरकर वर्ष 2014-15 (दूसरी तिमाही) में 98.9 अमरीकी डॉलर प्रति बीबीएल रही। आयातों के संबंध में विगत वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्द्ध की दो तिमाहियों में परिणाम पुनः कुछ मिला-जुला रहा। यह प्रमुखतः 2013-14 की प्रथम तिमाही में सोने के उच्च आयातों के मूल प्रभाव और वर्ष 2014-15 की प्रथम तिमाही में स्थिर वृद्धि के विपरीत वर्ष 2013-14 की दूसरी तिमाही में इन निर्यातों में

तीव्र सुधार के कारण हुआ जिसके बाद दूसरी तिमाही में आयात में वृद्धि हुई। परिणामतः मौसमी मांग में तेजी आई और सोने के आयातों पर प्रतिबंधों में ढील दी गई। यह मिला-जुला परिणाम भी वर्ष 2013-14 में दबाव के चलते वर्ष 2014-15 में गैर-सोना गैर-पीओएल आयातों में वृद्धि के कारण रहा। अदृश्य आयात-निर्यात खाते में (क) सेवाएं, (ख) अंतरण और (ग) आय शामिल हैं। इनमें अधिशेष, एक बड़ा कारक रहा है जिससे बड़े व्यापार घाटे को चालू खाता घाटे में जमा

होने से नियंत्रित किया गया। सेवाओं (निवल) पर सॉफ्टवेयर निर्यातकों का वर्चस्व बना रहा और इसमें पिछले वर्ष की उसी अवधि में 35.2 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले वर्ष 2014-15 (अप्रैल-सितम्बर) में 2.4% वृद्धि के साथ वृद्धि 36.0 बिलियन अमरीकी डालर रही। अंतरण (निवल) अधिकांश विप्रेषित धन 2013-14 और 2014-15 दोनों वर्षों के पूर्वाद्ध में लगभग 32.7 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। जबकि सॉफ्टवेयर सेवाएं और विप्रेषित धन अधिशेष प्रदान करते हैं, निवल आय एक व्यय है जो देय ब्याज/लाभांश को प्रतिबिंबित करता है और इसका निवल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के स्तर पर बहुत बड़ा संबंध है। आय (निवल) पर निवेश आय का वर्चस्व है और यह 2013-14 (अप्रैल-सितम्बर) में 13.4 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले 2014-15 (अप्रैल-सितम्बर) में 13.8 बिलियन अमरीकी डॉलर थी। उपर्युक्त गतिविधियों के परिणामस्वरूप, चालू खाता घाटा वर्ष 2013-14 की उसी अवधि में (अप्रैल-सितम्बर) 26.9 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले 2014-15 (अप्रैल-सितम्बर) में 17.9 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। जीडीपी के समानुपात में, चालू खाता घाटा वर्ष 2013 के पूर्वाद्ध में 3.1% से घटकर 2014-15 के पूर्वाद्ध में 1.9% रह गया।

वर्ष 2014-15 (अप्रैल-सितम्बर) में पूंजी/वित्त खाता संबंधी गतिविधियां

4.31 वर्ष 2014-15 के पूर्वाद्ध में मात्रा और गुणवत्ता दोनों मानदंडों के अनुसार निवल पूंजी/वित्तीय आवकों में अच्छा-खासा सुधार था। वर्ष 2013-14 के पूर्वाद्ध में निवल वित्तीय प्रवाह 16.3 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2014-15 के पूर्वाद्ध में 36.0 बिलियन अमरीकी डॉलर था। निवल विदेशी निवेश एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रवाह है जो वर्ष 2013-14 (अप्रैल-सितम्बर) में 7.8 बिलियन अमरीकी डॉलर से वर्ष 2014-15 (अप्रैल-सितम्बर) में अत्यधिक बढ़कर 38.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। निवल बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) भुगतान संतुलन के पूंजी/वित्त खाता की अन्य महत्वपूर्ण मद थी जो 2013-14 (अप्रैल-सितम्बर) में 2.5 बिलियन अमरीकी डालर से सुधर कर 2014-15 (अप्रैल-सितम्बर) में 3.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गई। निवल बैंकिंग पूंजी में गिरावट देखी गई जो 11.5 बिलियन अमरीकी डालर से गिरकर उसी अवधि में (-) 0.5 बिलियन अमरीकी डालर रह गई।

4.32 वित्तीय खाते पर प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो निवेशों का वर्चस्व था जो कि ऋण-भिन्न सृजक प्रकृति के हैं। इस

अवधि के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और पोर्टफोलियो निवेश के रूप में निवल प्रवाह चालू खाता घाटे के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त से अधिक थे। हालांकि उच्चतर निवल एफडीआई प्रवाह घरेलू अर्थव्यवस्था की वृद्धि संभाव्यता के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण प्रतिबिंबित करते हैं, 2014-15 में सुदृढ़ पोर्टफोलियो अंतर्वाहों को घरेलू अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्र की कम भेद्यताओं और यूरोपीय केन्द्रीय बैंक की अतिरिक्त सुगमता की प्रत्याशा से बनी हितैषी वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों का आधार मिला था। निवल पूंजी प्रवाहों और चालू खाता घाटा के स्तरों को देखते हुए मुद्रा भंडार में 2013-14 (अप्रैल-सितम्बर) में 10.7 बिलियन अमरीकी डॉलर की गिरावट के मुकाबले 2014-15 के पूर्वाद्ध में विदेशी मुद्रा भंडार में अभिवृद्धि (बीओपी आधार पर) 18.1 बिलियन अमरीकी डॉलर हुई। वर्ष 2014-15 (दिसम्बर 2014 तक) में, विदेशी संस्थागत निवेशकों में 28.5 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवल अंतर्वाह रहा जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2013-14 की तत्संगत अवधि में 4.5 बिलियन अमरीकी डॉलर का बहिर्वाह था। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह (निवल) पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़े अप्रैल-दिसम्बर 2014 की अवधि के लिए हैं जो वर्ष 2013-14 में उसी अवधि में 20.7 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले 24.2 बिलियन अमरीकी डॉलर पर थे। जहां तक अनिवासी भारतीय की जमा राशियों का संबंध है, वन-ऑफ स्वेप स्कीम के लिए समायोजित किये जाने पर यह अप्रैल-दिसम्बर 2013 (35.1 बिलियन अमरीकी डॉलर) के सापेक्ष अप्रैल-दिसम्बर 2014 में 10.0 बिलियन अमरीकी डॉलर के निम्न स्तर बहुत कुछ वही रहीं। चालू और पूंजी खातों में उपर्युक्त गतिविधियां चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वाद्ध के बाद भुगतान संतुलन आधार पर मुद्रा भंडार में आगे और अनुवृद्धि की ओर संकेत करती हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार

4.33 हालांकि वर्ष 2013-14 में, आरक्षित निधि में काफी गिरावट के चलते वर्ष की शुरुआत में रुपये का तीव्र मूल्यहास देखा गया, फिर भी सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार के संचय में वृद्धि हुई जो मार्च, 2013 के अंत में 292.0 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर की तुलना में मार्च 2014 के अंत में 304.2 बिलियन अमरीकी डॉलर था। 2014-15 के पूर्वाद्ध में, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भुगतान संतुलन के आधार पर (अर्थात् मूल्यांकन प्रभाव को

सारणी 4.5 : विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तनों का सार (बिलियन अमरीकी डालर)

क्रम सं०	वर्ष	वित्त वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार (मार्च के अंत में)	आरक्षित निधि में कुल वृद्धि (+) / कमी (-) आरक्षित निधि	बीओपी के आधार पर आरक्षित निधि में वृद्धि/कमी	मूल्यांकन प्रभाव के कारण में वृद्धि/कमी
1	2007-08	309.7	110.5	92.2	18.3
2	2008-09	252.0	-57.7	-20.1	-37.6
3	2009-10	279.1	27.1	13.4	13.7
4	2010-11	304.8	25.7	13.1	12.6
5	2011-12	294.4	-10.4	-12.8	2.4
6	2012-13	292.0	-2.4	3.8	-6.2
7	2013-14	304.2	12.2	15.5	-3.3
8	2014 सित. के अंत में	313.8	9.6	18.1	-8.5

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

सारणी 4.6: कुछ प्रमुख देशों का विदेशी मुद्रा भंडार

क्रम सं०	देश	दिसम्बर, 2014 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन अमरीकी डॉलर)
1.	चीन	3840.0#
2.	जापान	1312.1
3.	स्विट्ज़रलैंड*	526.6
4.	रूस महासंघ	388.5
5.	ब्राजील	363.6
6.	कोरिया गणराज्य*	363.2
7.	चीन, पी.आर. हांग-कांग*	344.6
8.	भारत	320.6
9.	जर्मनी	192.7
10.	थाईलैंड	163.7
11.	फ्रांस*	161.6
12.	इटली*	143.3

स्रोत : भारत और चीन को छोड़कर आईएमएफ

टिप्पणी : *नवीनतम आंकड़े केवल नवम्बर, 2014 माह के लिए उपलब्ध है। #www.pbc.gov.in

छोड़कर) 18.1 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई। तथापि, नाममात्ररूप से (अर्थात् मूल्यांकन प्रभाव सहित), सितम्बर के अंत में 313.8 बिलियन अमरीकी डालर में केवल 9.6 बिलियन अमरीकी डालर को वृद्धि थी। (सारणी 4.5)

4.34 चालू खाता घाटे वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, ब्राजील के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है (सारणी 4.6)। जनवरी अंत में, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 328.7 बिलियन अमरीकी डालर का है जिसमें 303.3 बिलियन अमरीकी डालर राशि की विदेशी मुद्रा

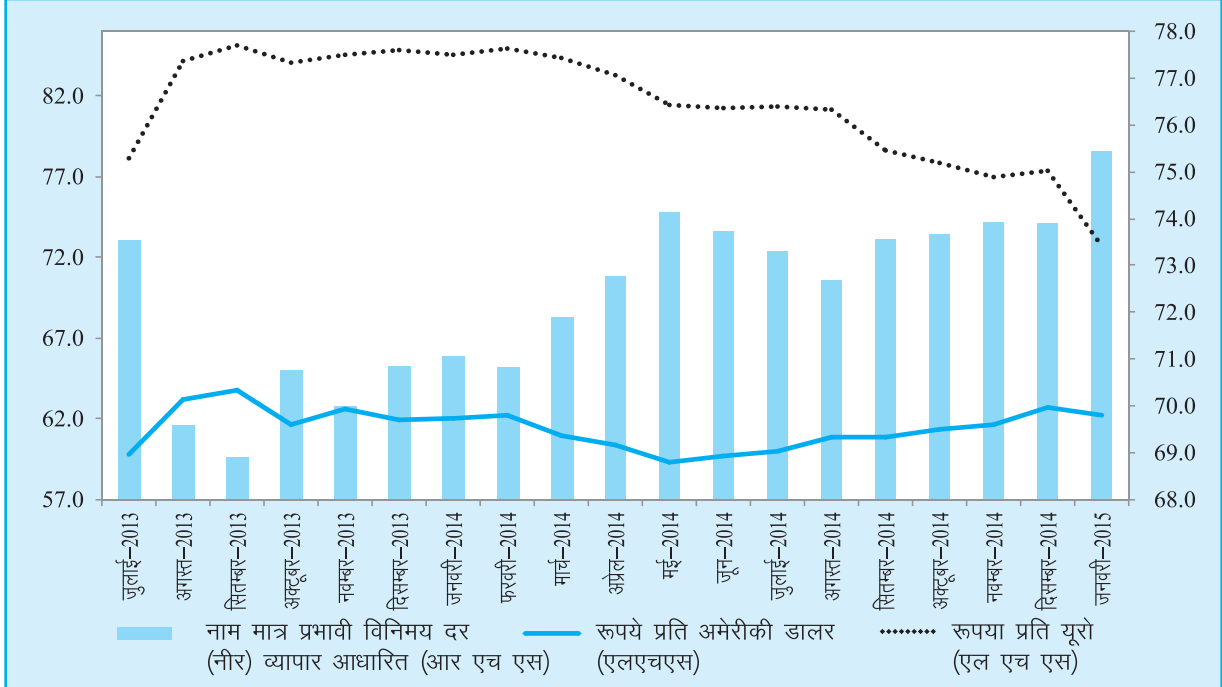
आस्तियां शामिल हैं जो कुल का 92.3 प्रतिशत बैठती हैं। वर्ष 2014-15 की पहली छमाही में आरक्षित निधि में वृद्धि के साथ, आरक्षित निधि आधारित सभी पारम्परिक बाह्य क्षेत्र की दुर्बलताओं के संकेतकों में सुधार आया है। उदाहरण के लिए, आरक्षित निधि के अनुपात में अल्पावधि विदेशी ऋण मार्च, 2014 के अंत में 29.3 प्रतिशत से घट कर सितम्बर, 2014 के अंत में 27.5 प्रतिशत रह गया है। आयात हेतु आरक्षित निधि का दायरा भी मार्च, 2014 के अंत में 7.8 माहों से बढ़कर सितम्बर, 2014 के अंत में 8.1 माहों का हो गया है।

विनिमय दर

4.35 2013-14 में, यूएस फेडरल द्वारा मात्रात्मक सुगमता को वापस लेने की इसकी मंशा के बारे में मई, 2013 में की गई घोषणा के बाद आयी वैश्विक अतनिश्चितता के फलस्वरूप चालू खाता घाटा (सीएडी) के स्तरों द्वारा यथा इंगित बाह्य वित्तपोषण अपेक्षा के आधार पर विभिन्न घटत-बढ़त के साथ उभर रहे बाजारों की मुद्राओं में मूल्यहास हुआ। चूंकि भारत में 2011-13 में सीएडी का स्तर बढ़ा हुआ था, जो 2013-14 की प्रथम तिमाही तक बना रहा, अंतः अमरीकी डॉलर की तुलना में रुपए की मासिक विनिमय दर अप्रैल 2013 के 54.38 रु. प्रति अमरीकी डॉलर से सितम्बर, 2013 में 63.75 रु. प्रति अमरीकी डॉलर होकर 14.7 प्रतिशत के मूल्यहास को दर्शाती है। तत्पश्चात्, मार्च, 2014 के अंत में यह दर स्थिर होकर 60.10 रु. तक पहुंची तथा अप्रैल, 2014 में यह 60.36 रु. प्रति अमरीकी डॉलर रही।

4.36 वर्ष के दौरान, रुपए-अमरीकी डॉलर की विनिमय दर, इक्विटी और बॉन्ड के बाजारों में हुए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी संस्थागत निवेशकों के विशाल अंतर्वाह के

चित्र 4.1: यूएस डालर, यूरो और नाममात्र प्रभावी विनिमय दर की तुलना में रुपये में उतार-चढ़ाव



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

कारण मोटे तौर पर स्थिर बनी रही। यूरोप और जापान में कमजोर आर्थिक निष्कर्षों के कारण, अमरीकी डॉलर की तुलना में यूरो और येन की परस्पर लेन-देन की मौद्रिक गतिविधियों के आगे-पीछे रहते हुए, सितम्बर, 2014 से इन दोनों के मुकाबले रुपये में मूल्यवृद्धि हुई है। 28 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार बिन्दु-दर-बिन्दु आधार पर रुपया 60.10 रु. प्रति अमरीकी डॉलर के स्तर से गिरकर 13 फरवरी, 2015 को 62.14 रु. प्रति अमरीकी डालर रह गया जो 3.3 प्रतिशत के मूल्यहास को दर्शाता है। 30 दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार, रुपया 63.75 रु. प्रति अमरीकी डॉलर के निम्न स्तर पर पहुंचा और 19 मई, 2014 को 58.43 रु. प्रति अमरीकी डालर के शीर्ष स्तर तक पहुंचा। माह-दर-माह आधार पर मार्च, 2014 में रुपया 61.01 रु. प्रति अमरीकी डॉलर के स्तर से लुढ़ककर जनवरी, 2015 में 62.23 रु. प्रति अमरीकी डॉलर रह गया जो 2.0 प्रतिशत के मूल्यहास को दर्शाता है। (चित्र 4.1)। फिर भी, रुपये में मार्च, 2014 से जनवरी, 2015 के बीच पाउंड स्टर्लिंग, यूरो और जापानी येन के मुकाबले क्रमशः 7.3 प्रतिशत, 16.1 प्रतिशत और 13.6 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई है। अप्रैल, 2014 से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले रुपए की माह-वार विनिमय दर और आरबीआई की विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा का क्रय/विक्रय सारणी 4.7 में दिया गया है।

4.37 कुल मिलाकर, रुपए ने ऊपर उल्लिखित बाह्य क्षेत्र के सुदृढ़ परिणामों के मद्देनजर वैश्विक घटनाओं के प्रति

लचीलेपन का प्रदर्शन किया है। मई, 2013 में, यूएस फेडरल के टैपर टॉक का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका से रुपए में भारी गिरावट आयी जबकि वास्तव में टैपर टॉप होने के पश्चात् रुपया स्थिर हो गया। 8 जनवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रुपए में मार्चांत, 2014 पर रूसी रूबल (40.4 प्रतिशत), ब्राजील रियाल (14.2 प्रतिशत), मेक्सिकन पेसो (10.7 प्रतिशत), इंडोनेशियाई रूपियाह (10.4 प्रतिशत) और दक्षिण अफ्रीकी रैंड (8.5 प्रतिशत) की तुलना में अमरीकी डॉलर के मुकाबले 4.6 प्रतिशत का मामूली मूल्यहास हुआ। (परिशिष्ट सारणी 6.4)।

4.38 प्रभावी विनिमय दरें व्यापार के विभिन्न साझेदार देशों के विविध मुद्रा समूह की तुलना में घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव की संक्षिप्त संकेतक होती हैं तथा इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता का सूचक माना जाता है। वास्तविक प्रभाव विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक एक समयावधि के दौरान देश की बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता के संकेतक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नाममात्र प्रभावी विनिमय दर, (एनईईआर) विदेशी मुद्राओं के संबंध में घरेलू मुद्रा की द्विपक्षीय नाममात्र विनिमय दरों की भारत ज्यामितीय औसत होती है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर को सापेक्ष कीमत भिन्नता हेतु समायोजित विदेशी मुद्राओं के संबंध में घरेलू मुद्रा की नाममात्र विनिमय दरों के भारत ज्यामितीय औसत के रूप में परिभाषित किया जाता है। हालांकि, रुपए में अमरीकी डॉलर की तुलना में मूल्यहास हुआ है, फिर भी, नाममात्र प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) (36 मुद्राएं) के अनुसार इसमें मार्च, 2014 की

तालिका 4.7 : वर्ष 2014-15 के दौरान विदेशी मुद्रा के मुकाबले रुपए की विनिमय दरें तथा आरबीआई द्वारा किया गया अमरीकी डॉलर का क्रय/विक्रय

माह	औसत विनिमय दर (रुपए प्रति विदेशी मुद्रा) ^क					आरबीआई का निवल विक्रय(-) क्रय(+) (मिलियन अमरीकी डॉलर)
	अमरीकी डॉलर	पाउंड स्टर्लिंग	यूरो	जापानी येन ^ख		
1	2	3	4	5	6	
2013-14 (वार्षिक औसत)	60.50	96.31 (-10.1)	81.17 (-10.7)	60.40 (-13.7)	8992 (9.0)	
2014-15 (मासिक औसत)						
अप्रैल, 2014	60.36 (1.1)	101.08 (0.3)	83.35 (1.2)	58.86 (1.3)	5870	
मई, 2014	59.31 (1.8)	99.94 (1.1)	81.49 (2.3)	58.28 (1.0)	1786	
जून 2014	59.73 (-0.7)	100.98 (-1.0)	81.24 (0.3)	58.53 (-0.4)	2642	
जुलाई 2014	60.06 (-0.5)	102.62 (-1.6)	81.39 (-0.2)	59.07 (-0.9)	5453	
अगस्त, 2014	60.90 (-1.4)	101.81 (0.8)	81.14 (0.3)	59.17 (-0.2)	-511	
सितम्बर, 2014	60.86 (0.05)	99.31 (2.5)	78.60 (3.2)	56.77 (4.2)	1437	
अक्तूबर, 2014	61.34 (-0.8)	98.72 (0.6)	77.91 (0.9)	56.87 (-0.2)	2703	
नवम्बर, 2014	61.70 (-0.6)	97.28 (1.5)	76.99 (1.2)	53.05 (7.2)	3081	
दिसम्बर, 2014	62.75 (-1.7)	98.11 (-0.8)	77.36 (-0.5)	52.60 (0.9)	6739	
जनवरी, 2015	62.23 (0.8)	94.54 (3.8)	72.77 (6.3)	52.54 (0.1)	—	

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणियां : उ.प.: उपलब्ध नहीं है

क भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) बाजार संकेतक दरें। मई, 2012 से आगे के आंकड़े आरबीआई की संदर्भ दरें हैं।

ख प्रति 100 येन

कोष्ठकों में आंकड़े पूर्व माह/वर्ष के दौरान मूल्यवृद्धि (+) और मूल्यहास (-) प्रतिशतता में दर्शाते हैं।

पूर्णांक के कारण आंकड़े भिन्न हो सकते हैं।

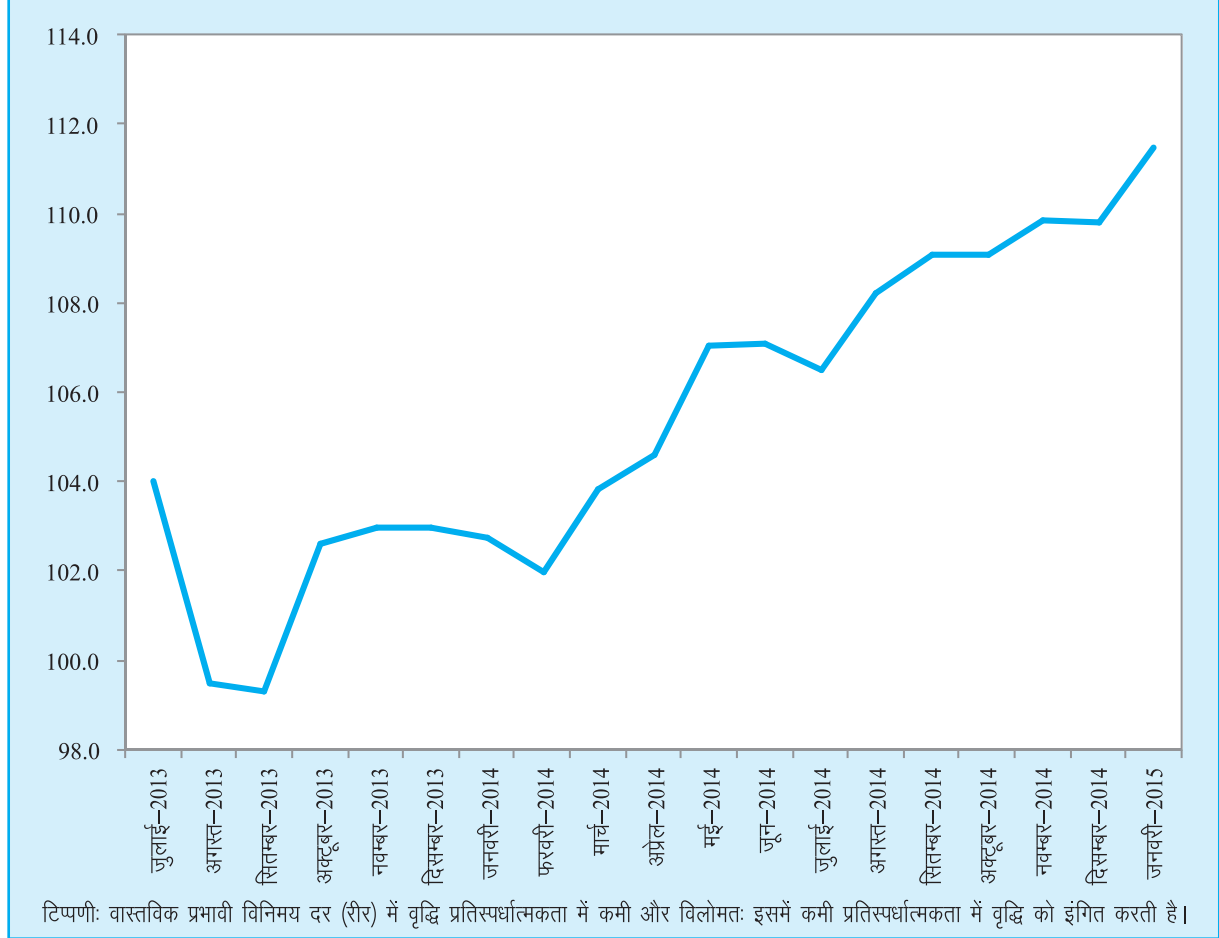
तुलना में दिसम्बर, 2014 में 2.8 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई है। इसी तरह, इसी अवधि के दौरान वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में भी 5.8 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई (चित्र 4.2)

विदेशी ऋण

4.39 1991 के भुगतान संतुलन (बीओपी) संकट के बाद, स्थिरता, ऋण चुकाने की क्षमता और नकदी पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत की विवेकपूर्ण विदेशी ऋण नीतियों एवं प्रबंध ने विदेशी ऋण के बढ़ते आकार को सामान्य स्तर

तक लाने में मदद की है तथा यह बड़ी अवधि की परिपक्वता प्रोफाइल के साथ मुद्रासंयोजन के रूप से बेहतर है। मार्च, 2014 की समाप्ति पर भारत का कुल विदेशी ऋण भंडार 442.3 बिलियन अमरीकी डॉलर का था जो मार्चांत, 2013 के स्तर की तुलना में 32.8 बिलियन अमरीकी डॉलर (8.0 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है। इस अवधि के दौरान, कुल विदेशी ऋण में हुई वृद्धि दीर्घावधि ऋण विशेषकर अनिवासी भारतीय जमाओं के कारण हुई थी। बाह्य वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सितम्बर से नवम्बर, 2013 के दौरान स्वैप स्कीम के अंतर्गत

चित्र 4.2: वास्तविक प्रभावी विनिमय दर व्यापार आधारित (36 मुद्राएं) 2004 - 05 = 100



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

जुलाई गई नई विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों (बैंकों) (एफसीएनआर(बी) जमाओं के चलते अनिवासी भारतीय जमाओं में काफी तेजी से वृद्धि हुई। मार्चांत, 2013 के स्तर के मुकाबले 12.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराते हुए मार्चांत 2014 में दीर्घावधि विदेशी ऋण 353.0 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जबकि अल्पावधि ऋण ने 7.7 प्रतिशत की गिरावट दर्शाई। परिशिष्ट 8.4(क) और 8.4 (ख) क्रमशः भारतीय रुपए और अमरीकी डॉलर में भारत के बकाया विदेशी ऋण के संबंध में अलग-अलग घटकों में आंकड़े प्रस्तुत करते हैं।

4.40 नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत का विदेशी ऋण भंडार मार्च, 2014 के अंत के स्तर से 13.7 बिलियन अमरीकी डॉलर (3.1 प्रतिशत) बढ़कर सितम्बर, 2014 के अंत में 455.9 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। विदेशी ऋण में वृद्धि का कारण अधिक दीर्घावधि ऋण विशेषकर वाणिज्यिक उधारों और एनआरआई जमाएं थीं। भारत के विदेशी ऋण का परिपक्वता प्रोफाइल दीर्घावधि उधारों की

अधिकता की ओर संकित करता है। मार्च, 2014 के अंत में 79.8 प्रतिशत की तुलना में सितम्बर, 2014 के अंत में दीर्घावधि ऋण, कुल विदेशी ऋण का 81.1 प्रतिशत बैठता था। कुल विदेशी ऋण में अल्पावधि ऋण का हिस्सा मार्च, 2014 के अंत में 20.2 प्रतिशत से घटकर सितम्बर, 2014 के अंत में 18.9 प्रतिशत रह गया। भारत के विदेशी ऋण के संयोजन का ब्यौरा सारणी 4.8 में दिया गया है।

4.41 भारत के कुल विदेशी ऋण का मुद्रा संयोजन यह दर्शाता है कि विदेशी ऋण भंडार में सितम्बर, 2014 के अंत में सबसे अधिक हिस्सा 60.1 प्रतिशत अमरीकी डॉलर का है, जिसके बाद भारतीय रुपया (24.2 प्रतिशत), विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) (6.5 प्रतिशत), जापानी येन (4.5 प्रतिशत) और यूरो (3.0 प्रतिशत) का हिस्सा आता है। सरकारी (सॉवरेन) ऋण का मुद्रा संयोजन दर्शाता है कि एसडीआर मुद्रा वाला ऋण का (33.5 प्रतिशत) पहले से बड़ा हिस्सा रहता आया है जो अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (आईडीए) से उधार यानि बहुपक्षीय एजेंसियों के तहत विश्व

सारणी 4.8: विदेशी ऋण के संघटक

(कुल विदेशी ऋण की तुलना में प्रतिशतता)

क्रम सं.	संघटक	मार्च, 2012	मार्च, 2013आ.सं.	मार्च, 2014आ.सं.	सितम्बर 2014त्व.अ.
1	2	3	4	5	6
1.	बहुपक्षीय	14.0	12.6	12.1	11.7
2.	द्विपक्षीय	7.4	6.1	5.6	5.1
3.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	1.7	1.5	1.4	1.3
4.	निर्यात ऋण	5.3	4.3	3.5	3.4
5.	वाणिज्यिक उधारें	33.3	34.2	33.5	35.4
6.	एनआरआई जमाएं	16.2	17.3	23.5	23.8
7.	रुपया ऋण	0.4	0.3	0.3	0.3
8.	दीर्घावधि ऋण (1 से 7)	78.3	76.4	79.8	81.1
9.	अल्पावधि ऋण	21.7	23.6	20.2	18.9
10.	कुल विदेशी ऋण (8+9)	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत : वित्त मंत्रालय एवं भारतीय रिज़र्व बैंक

आ.सं.: आंशिक संशोधन, त्व.अ.- त्वरित अनुमान

बैंक की सॉफ्ट ऋण विंडो और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा एसडीआर के आबंटनों के कारण है। सितम्बर, 2014 के अंत में, सरकारी (सॉवरेन) विदेशी ऋण 88.4 बिलियन अमरीकी डॉलर था। यह भारत के कुल विदेशी ऋण का 19.4 प्रतिशत बैठता था। गैर-सरकारी विदेशी ऋण 367.5 बिलियन अमरीकी डॉलर बैठता था जो सितम्बर, 2014 के अंत में, कुल विदेशी ऋण का 80.6 प्रतिशत था।

4.42 इन वर्षों में, भारत के विदेशी ऋण के भंडार में संयोजन संबंधी संरचनात्मक बदलाव आए हैं। कुल ऋण में रियायत का अनुपात 1991-2000 की अवधि के दौरान के 42.9 प्रतिशत (औसत) से गिरकर 2001-2010 में 28.1 प्रतिशत हो गया और सितम्बर, 2014 के अंत में और गिरकर 9.8 प्रतिशत हो गया। कुल विदेशी ऋण में गैर-सरकारी हिस्से के ज्यादा होने का इस तथ्य का पता चलता है कि ऐसा ऋण ही 1990 दशक में 45.3 प्रतिशत के मुकाबले 2000 के दशक के दौरान कुल बजट का 65.6 प्रतिशत हिस्सा था। गत पांच वर्षों में, गैर-सरकारी ऋण कुल ऋण का 70 प्रतिशत से अधिक था जो सितम्बर, 2014 के अंत में 80.6 प्रतिशत रहा। विदेशी ऋण के प्रमुख संकेतकों को तालिका 4.9 में दर्शाया गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च, 2014 के अंत में 68.8 प्रतिशत की तुलना में सितम्बर, 2014 के अंत में कुल विदेशी ऋण भंडार का 68.9 प्रतिशत बैठता है। विदेशी मुद्रा भंडार के अनुपात में अल्पावधि विदेशी ऋण मार्च, 2014 के अंत में 29.3 प्रतिशत के मुकाबले सितम्बर, 2014 के अंत में 27.5 प्रतिशत था। कुल विदेशी ऋण के

अनुपात में रियायती ऋण में धीरे-धीरे लगातार गिरावट आई और यह मार्च, 2014 के अंत में 10.5 प्रतिशत की तुलना में दिसम्बर, 2014 के अंत में 9.8 प्रतिशत रह गया।

4.43 2013-14 में के स.घ.उ. के अनुपात में विदेशी ऋण 23.5 प्रतिशत होने तथा ऋण सेवा अनुपात का 5.9 प्रतिशत होने से यह इंगित होता है कि भारत का विदेशी ऋण हमेशा प्रबंधनीय सीमाओं के अंदर बना रहा है। भारत सरकार की विवेकपूर्ण विदेशी ऋण की प्रबंध नीति ने विदेशी ऋण की बढ़ोतरी को सीमित करने और विदेशी ऋण की सुविधाजनक स्थिति बनाए रखने में मदद की है। इस नीति में दीर्घ एवं अल्पावधि ऋण पर नजर रखने, लम्बी परिपक्वताओं के साथ रियायती शर्तों पर सॉवरेन ऋण जुटाने, अंतिम उपयोग, समग्र-लागत और परिपक्वता प्रतिबंधनों के माध्यम से विदेशी वाणिज्यिक उधारों को विनियमित करने तथा अनिवासी भारतीय जमाओं की ब्याज दरों को तर्कसंगत बनाने पर ध्यान दिया जाता रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय तुलना

4.4 वर्ष 2013 हेतु, विदेशी ऋण के आंकड़ों वाला, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी 2015 प्रकाशन के आधार पर विदेशी ऋण के संबंध में देशों की परस्पर तुलना यह दर्शाती है कि भारत अभी भी कम भेदनीय देशों में बना हुआ है। भारत के ऋण के प्रमुख संकेतक अन्य ऋणी विकासशील देशों के मुकाबले बेहतर हैं। सकल राष्ट्रीय आय के अनुपात

सारणी 4.9 : भारत के विदेशी ऋण के प्रमुख संकेतक

(प्रतिशतता)

वर्ष	विदेशी ऋण (बिलियन यूएस डॉलर	स.घ.उ. कुल विदेशी	ऋण सेवा अनुपात	कुल विदेशी ऋण के विदेशी विनिमय	कुल विदेशी ऋण में रियायती ऋण प्रारक्षित निधि	विदेशी विनिमय प्रारक्षित निधि में	कुल ऋण में अल्पावधि विदेशी ऋण अल्पावधि विदेशी ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8
2010-11	317.9	18.2	4.4	95.9	14.9	21.3	20.4
2011-12	360.8	20.9	6.0	81.6	13.3	26.6	21.7
2012-13 PR	409.5	22.3	5.9	71.3	11.1	33.1	23.6
2013-14 PR	442.3	23.5	5.9	68.8	10.5	29.3	20.2
सित. 2014 अंत में त्व.अ.	455.9	-	-	68.9	9.8	27.5	18.9

टिप्पणी : आं.स.-आंशिक संशोधित; त्व.अ.- त्वरित अनुमान - : वर्ष के भाग हेतु नहीं निकाला गया

* : अल्पावधि ऋण मूल परिपक्वता पर आधारित है।

ऋण-सेवा अनुपात, विदेशी चालू प्राप्तियों को किया जाने वाला सकल ऋण सेवा संदाय का अनुपात होता है। (सरकारी हस्तांतरणों का निवल)

में भारत का विदेशी ऋण भंडार 23.0 प्रतिशत रहते हुए छठे स्थान पर है। विदेशी ऋण में विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली राशि के अनुसार, भारत का स्थान 64.7

प्रतिशत के साथ ऊपर से छठें स्थान पर था। (अतिरिक्त विवरण हेतु कृपया [http://www.finmin.nic.in \(reports/indExtdebt.asp\)](http://www.finmin.nic.in (reports/indExtdebt.asp) वेबसाइट देखें)